

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2019—माघ 26, शक 1940

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2019

क्रमांक ई-1-22/2018/एक-2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा 2010 बैच के निम्नांकित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1)(2) के परन्तुक के अंतर्गत आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम क्रमांक-4 में अंकित तिथि से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान Pay Matrix Level-12 में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त,

स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं आबंटन वर्ष	वर्तमान पदस्थापना	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान की देय तिथि
1.	श्री जयप्रकाश मौर्य (2010)	कलेक्टर, जिला सुकमा	01-01-2019
2.	श्री कार्तिकेय गोयल (2010)	संचालक, पंचायत तथा अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय का अति. प्रभार संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) का अति. प्रभार.	01-01-2019
3.	सुश्री रानू साहू (2010)	कलेक्टर, कांकेर	01-01-2019
4.	श्री सारांश मित्र (2010)	कलेक्टर, जिला सरगुजा	01-01-2019
5.	श्री पदुम सिंह एल्मा (2010)	कलेक्टर, जिला नारायणपुर	01-01-2019
6.	श्री रमेश कुमार शर्मा (2010)	उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय तथा आति. प्रभार संचालक, भू-अभिलेख.	01-01-2019
7.	श्री धर्मेस कुमार साहू (2010)	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक	01-01-2019

2. सरल क्रमांक 7 पर दर्शित अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत उनके नाम के सम्मुख दर्शाए नवीन पदस्थापना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. उपरोक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में अनिवार्यतः भाग लेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कमल प्रीत सिंह, सचिव.**

### महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाए अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बेमेतरा	बेमेतरा	श्री सुमीत कुमार हर्षयाना, सिविल जज, क्लास-II, साजा

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chairman (Principal Magistrate), mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bemetara	Bemetara	Shri Sumit Kumar Harsyana, Civil Judge Class-II, Saja

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गरियाबंद	गरियाबंद	श्री विवेक नेताम, जेएमएफसी, राजिम

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chairman (Principal Magistrate), mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gariyaband	Gariyaband	Shri Vivek Netam, JMFC Rajim

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. गीता, सचिव.

**गृह (पुलिस) विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर**

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्रमांक/एफ 01-09/2018/दो-गृह/भापुसे.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक I-15011/14/2012-IPS-I (Part-I) दिनांक 14-03-2018 द्वारा सिलेक्ट लिस्ट 2008, 2009, 2010 एवं 2011 के लिये राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में चयनित निम्नांकित अधिकारियों की वरिष्ठता में परिवर्तन करते हुये उनके नाम के सामने कालम नं. 5 में अंकित अनुसार संशोधित आवंटन वर्ष प्रदान करने के फलस्वरूप आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर परिणामी लाभ के तहत उनके नाम के सामने कॉलम नं. 6 में उल्लेखित दिनांक से भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3(2) (ii) के अंतर्गत, सेवा का चयन श्रेणी वेतनमान (पे बैंड 37,400-67,000+ग्रेड पे रु. 8,700/-) (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 रु. 01,18,500-02, 14, 100) प्रदान किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	सिलेक्ट लिस्ट	पूर्व में आवंटित वर्ष	संशोधित आवंटित वर्ष	चयन श्रेणी वेतनमान प्रदान करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	श्री ए. एम. जूरी	2008	2000	1999	01-01-2012
02.	श्री पी. के. दास	2008	2001	2000	01-01-2013
03.	श्री के. सी. अग्रवाल	2009	2002	2001	01-01-2014
04.	श्री के. के. अग्रवाल	2009	2002	2001	01-01-2014
05.	श्री एस. एस. सोरी	2010	2003	2002	01-01-2015
06.	श्री टी. आर. पैकरा	2010	2003	2002	01-01-2015
07.	श्री डी. एल. मनहर	2010	2004	2003	01-01-2016
08.	श्री आर. एस. नायक	2010	2004	2003	01-01-2016
09.	श्री जी. एस. दर्श	2010	2004	2003	01-01-2016
10.	श्री नरेन्द्र खरे	2010	2004	2003	01-01-2016
11.	श्री एस. सी. द्विवेदी	2010	2004	2003	01-01-2016
12.	श्री जे. एस. वट्टी	2010	2004	2003	01-01-2016
13.	श्री ए. आर. कोराम	2010	2004	2003	01-01-2016
14.	श्री आर. पी. साय	2010	2004	2003	01-01-2016
15.	श्री संजीव शुक्ला	2011	2005	2004	01-01-2017
16.	श्री एच. आर. मनहर	2011	2005	2004	01-01-2017

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्रमांक/एफ 01-09/2018/दो-गृह/भापुसे.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक I-15011/14/2012-IPS-I (Part-I) दिनांक 14-03-2018 द्वारा सिलेक्ट लिस्ट 2008, 2009, 2010 एवं 2011 के लिये राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में चयनित निम्नांकित अधिकारियों की वरिष्ठता में परिवर्तन करते हुये उनके नाम के सामने कालम नं. 5 में अंकित अनुसार संशोधित आवंटन वर्ष प्रदान करने के फलस्वरूप आवंटन वर्ष से 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर परिणामी लाभ के तहत उनके नाम के सामने कॉलम नं. 6 में उल्लेखित दिनांक से सेवा के उप पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान (पे बैंड-4 रुपये 37400-67000+ग्रेड पे रुपये 8,900/-) (पुनरीक्षित अनुसूची-III

वेतन मैट्रिक्स-13क रुपये 01,31,100-02,16,600/-) प्रदान किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	सिलेक्ट लिस्ट	पूर्व में आवंटित वर्ष	संशोधित आवंटित वर्ष	चयन श्रेणी वेतनमान प्रदान करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	श्री पी. के. दास	2008	2001	2000	01-01-2014
02.	श्री के. सी. अग्रवाल	2009	2002	2001	01-01-2015
03.	श्री के. के. अग्रवाल	2009	2002	2001	01-01-2015
04.	श्री एस. एस. सोरी	2010	2003	2002	01-01-2016
05.	श्री टी. आर. पैकरा	2010	2003	2002	01-01-2016
06.	श्री डी. एल. मनहर	2010	2004	2003	01-01-2017
07.	श्री आर. एस. नायक	2010	2004	2003	01-01-2017
08.	श्री जी. एस. दर्दो	2010	2004	2003	01-01-2017
09.	श्री एस. सी. द्विवेदी	2010	2004	2003	01-01-2017
10.	श्री ए. आर. कोराम	2010	2004	2003	01-01-2017
11.	श्री आर. पी. साय	2010	2004	2003	01-01-2017
12.	श्री संजीव शुक्ला	2011	2005	2004	01-01-2018
13.	श्री एच. आर. मनहर	2011	2005	2004	01-01-2018

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्रमांक-एफ 3-21/2018/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसुविधा तथा प्रशासनिक दृष्टि से, एतद्वारा, पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित पुलिस थाना, जिसकी प्रविष्टियां तत्स्थानीय कॉलम (4) तथा (5) में उल्लिखित हैं, को कॉलम (2) में उल्लिखित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार के रूप में अधिसूचित करती है :—

#### सारणी

स. क्र.	पुलिस थाना/तहसील/जिले का नाम, जिसमें स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना है	पुलिस थाना/तहसील/जिले का नाम, जिससे स्थानीय क्षेत्र को अपवर्जित किया जाना है	प्रस्तावित ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुलिस थाना-कुरुद	पुलिस थाना-अर्जुनी	ग्राम-बारना	11

No. F 3-21/2018/Home-II.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, in view of Public Convenience and Administration, hereby, notifies, by partial amendment in previous notification, the police station mentioned in column (3) having corresponding entries mentioned in column (4) and (5) as local jurisdiction of police station mentioned in

column (2) in the Table below :—

TABLE

S. No.	Name of Police Station/ Tehsil/District in which the local area has to be included	Name of Police Station/ Tehsil/District from which the local area has to be excluded	Name of the proposed village	Patwari Halka Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Police Station-Kurud	Police Station-Arjuni	Barna Village	11

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 1-06/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	श्री बालाजी राव सोमावार भापुसे-2007	सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	पुलिस अधीक्षक, जिला-धमतरी
02.	श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला भापुसे-2011	पुलिस अधीक्षक जिला-नारायणपुर	पुलिस अधीक्षक ई.ओ. डब्ल्यू. रायपुर
03.	श्री रजनेश सिंह, भापुसे	पुलिस अधीक्षक, जिला-धमतरी	पुलिस अधीक्षक जिला-नारायणपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2019

क्रमांक-एफ 3-28/2018/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसुविधा तथा प्रशासनिक दृष्टि से, एतद्वारा, पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित पुलिस थाना, जिसकी प्रविष्टियां तत्स्थानी कॉलम (4) तथा (5) में उल्लिखित हैं, को कालम (2) में उल्लिखित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार के रूप में अधिसूचित करती है :—

सारणी

स. क्र.	पुलिस थाना/तहसील/जिले का नाम, जिसमें स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना है	पुलिस थाना/तहसील/जिले का नाम जिससे स्थानीय क्षेत्र को अपवर्जित किया जाना है	प्रस्तावित ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुलिस थाना-कुण्डा तहसील-पण्डरिया जिला-कबीरधाम	पुलिस थाना-पण्डरिया तहसील-पण्डरिया जिला-कबीरधाम	कोलेगांव	58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	पुलिस थाना-कवर्धा तहसील-कवर्धा जिला-कबीरधाम	पुलिस थाना-भोरमदेव तहसील-कवर्धा जिला-कबीरधाम	गंगचुआ	01

No. F 3-28/2018/Home-2.—In exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, in view of Public Convenience and Administration, hereby, notifies, by partial amendment in previous notification, the police station mentioned in column (3) having corresponding entries mentioned in column (4) and (5) as local jurisdiction of police station mentioned in column (2) in the Table below :—

TABLE

S. No.	Name of Police Station/ Tehsil/District in which the local area has to be included in	Name of Police Station/ Tehsil/District in which the local area has to be excluded from	Name of the proposed village	Patwari Halka Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Police Station-Kunda, Tehsil-Pandriya District-Kabirdham	Police Station-Pandriya Tehsil-Pandriya District-Kabirdham	Kolegaon	58
2.	Police Station-Kawardha, Tehsil-Kawardha District-Kabirdham	Police Station-Bhoramdev Tehsil-Kawardha District-Kabirdham	Gangchuva	01

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लीना कमलेश मंडावी, उप-सचिव.

### वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 5-12/2002/10-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-03-2016 द्वारा श्री रामप्रताप सिंह, को छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर का अध्यक्ष एवं डॉ. जे. पी. शर्मा, को छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

2. अतः श्री रामप्रताप सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर एवं डॉ. जे. पी. शर्मा, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर द्वारा उक्त पद से दिया गया त्यागपत्र राज्य शासन, एतद्द्वारा, दिनांक 14-12-2018 (अपराह्न) से स्वीकृत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. पी. राजपूत, अवर सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	खुटपदर प.ह.नं. 24	136.390	अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी., लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर.	एनएमडीसी 3.00 एमटीपीए इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के कर्मचारी/ अधिकारी के निवास हेतु स्थायी आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	माडपाल प.ह.नं. 25	83.160	अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी., लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर.	एनएमडीसी 3.00 एमटीपीए इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार के कार्यालय में किया जा सकता है.



बस्तर, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	धनपुंजी प.ह.नं. 28	170.260	अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी., लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर.	एनएमडीसी 3.00 एमटीपीए इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के स्टाकयार्ड जलाशय, वेस्ट डिस्पोजल प्लांट के निर्माण एवं वृक्षारोपण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्रमांक क/भू-अर्जन/07/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	चोकावाडा प.ह.नं. 29	78.180	अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी., लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर.	एनएमडीसी 3.00 एमटीपीए इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के कंस्ट्रक्शन कॉलोनी, प्रशिक्षण केन्द्र एवं फिनिशड प्रोडक्ट प्लांट के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कस्तुरी प.ह.नं. 29	2.440	अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी., लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर.	एनएमडीसी 3.00 एमटीपीए इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्रमांक क/भू-अर्जन/09/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मंगनपुर प.ह.नं. 26	2.340	अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी., लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर.	एनएमडीसी 3.00 एमटीपीए इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के इन प्लांट रेलवे लाईन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/अधिशायी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अय्याज तंबोली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2019

क्रमांक 1/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमाली प.ह.नं. 34	34.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा, के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजय अलंग**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरिया, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्रमांक 415/भू-अर्जन/रा.प्र.क्र.-09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला-कोरिया  
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-शंकरगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.860 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.37
4	0.39
9/1	0.12
9/2	0.12

(1)	(2)	कोरिया, दिनांक 21 जनवरी 2019	
9/3	0.12	क्रमांक 416/भू-अर्जन/रा.प्र.क्र.-10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
9/4	0.12		
9/5	0.12		
254	0.49		
255/1	0.50		
260/1	0.14		
260/2	0.13		
260/3	0.13		
260/4	0.13	अनुसूची	
280	2.02		
282	0.52	(1) भूमि का वर्णन—	
283	0.74	(क) जिला-कोरिया	
284	0.96	(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़	
289	0.23	(ग) नगर/ग्राम-डंगौरा	
290	0.39	(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.508 हेक्टेयर	
291	0.51	खसरा नम्बर	रकबा
292	0.53		(हेक्टेयर में)
294	0.91	(1)	(2)
295	0.77		
297	2.04	159	0.120
298	1.38	164	0.090
299/1	0.35	167	0.097
299/2	0.42	192	0.169
299/3	0.34	191	0.069
301	0.65	298	0.036
308	0.16	297	0.153
2	0.61	296	0.040
3	0.14	295	0.040
287	0.45	256	0.252
296	0.46	268	0.273
303	0.10	367	0.030
255/2	0.30	389/1/क/2	0.150
		389/1/क/3	0.045
		272	0.018
		389/1/ख	0.147
		389/2	0.030
योग	36	373/2	0.090
	17.86	375	0.210
		369	0.120
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शंकरगढ़		368	0.124
व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.		370/2	0.060
		370/1	0.030
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		370/10	0.030
(राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		370/9	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
371	0.055	344	0.048
		347	0.055
योग	26	370	0.139
		348	0.052
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शंकरगढ़		364	0.070
व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.		374/1/क	0.072
		506/1	0.150
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		386	0.069
(राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		377	0.045
		378	0.028
		380	0.022
		382	0.085
कोरिया, दिनांक 21 जनवरी 2019		405	0.165
		412	0.207
क्रमांक 417/भू-अर्जन/रा.प्र.क्र.-11/अ-82/2017-18.—चूंकि		516	0.165
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई		464	0.061
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में		463	0.052
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि		475	0.159
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता		462	0.180
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम		478/1	0.037
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित		507/3	0.079
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता		507/1	0.060
है :—		511/1	0.105
		511/2	0.189
		514	0.060
		479/1	0.042
		517	0.085
		479/2	0.060
		योग	41
			3.340

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़

(ग) नगर/ग्राम-भल्लौर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.340 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

66

0.015

67

0.030

65

0.048

68/2

0.050

68/1/ख

0.090

374/1/ख

0.066

506/2

0.055

69

0.060

329

0.085

330

0.020

328/2

0.030

341

0.075

345

0.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शंकरगढ़  
व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी  
(राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्रमांक 418/भू-अर्जन/रा.प्र.क्र.-12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

कोरिया, दिनांक 21 जनवरी 2019

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोरिया  
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-डोमनापारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
523	0.045
519	0.165
516	0.120
518	0.142
500	0.090
498	0.079
495	0.049
496	0.094
532/2	0.082
532/1	0.090
540	0.045
534	0.117
490/1	0.114
490/2	0.045
489	0.106
422	0.039
429	0.042
430	0.120
423	0.079
418/1	0.075
418/2	0.087
418/4	0.105
418/3	0.075
417	0.012
411/2	0.075
412	0.150
योग	26
	2.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शंकरगढ़ व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्रमांक 419/भू-अर्जन/रा.प्र.क्र.-13/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोरिया  
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-लालपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/1	0.288
96	0.118
98/2	0.052
99/1/ग	0.010
99/1/क	0.091
99/1/घ/1	0.065
99/1/घ/2	0.026
योग	7
	0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शंकरगढ़ व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्रमांक 420/भू-अर्जन/रा.प्र.क्र.-14/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोरिया  
(ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-चैनपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.368 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/4	0.024
11/1	0.060
12	0.030
26	0.132
13/1	0.120
16/3	0.036
16/6	0.048
27/1	0.132
27/5	0.132
29/3	0.018
34/6	0.084
32/2	0.018
34/1	0.144
34/3	0.054
152/2	0.156
152/1	0.060
165/2	0.042
148/2	0.006
147/1/ख	0.072
योग	19
	1.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शंकरगढ़  
व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी  
(राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र कुमार दुग्गा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्रमांक/01/अ-82/सन् 2017-2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बालोद  
(ख) तहसील-बालोद  
(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/10	0.12
14/7	0.10
22/2	0.01
14/6	0.30
21/4	0.04
14/13	0.14
13/17	0.08
18/5	0.02
23/7	0.05
17/11	0.05
18/3	0.01
14/5	0.05
14/10	0.02
18/6	0.03
21/2	0.04

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तरौद-दैहान बायपास मार्ग निर्माण कार्य लं. 7.80 कि.मी. हेतु.
33/25	0.10	
23/2	0.05	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.
51/3	0.16	
55/9	0.05	
योग	19	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

प्रारूप-घ  
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 114/बी. 121/2017-18.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 114 बी-121/2017-18 दिनांक 21-08-2018 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14 सितंबर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अभिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है और उक्त भूमिगत पाईपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.



और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली/33	173/3	0.085
योग कुल ख. नं.			1	कुल रकबा 0.085 हे.

बी. पी. जायसवाल,  
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय  
अधिकारी (रा.).

### उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th February 2019

No. 257/Confdl./2019/II-2-99/2001 (Pt.-III).—On the basis of application dated 18-09-2018 of Ku. Perna Ahire, Member of Lower Judicial Service, presently posted as I Civil Judge Class-II, Bastar (Jagdalpur) requesting for change of her home district, permission is hereby accorded to change her home district as “Raipur/Mungeli” instead of “Raipur” with a direction that in her service records, her home district be mentioned as “Raipur/Mungeli”.

By the order of Hon’ble the Chief Justice,  
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.